

SRG FINGROW FINANCE LIMITED

CIN: - L67120RJ1995PLC009631

**R.O. - 322, SM LODHA COMPLEX, NEAR SHASTRI CIRCLE, UDAIPUR,
RAJASTHAN, INDIA, 313001**

**Phone No: 0294-2561882, Email: srgsecurities@gmail.com,
Website: www.srgfin.com**

Date: 08-09- 2025

To,
BSE Limited
1st Floor, P.J. Towers,
Dalal Street,
Mumbai-400001

Subject: Publication of Newspaper Advertisement with regards to 30TMAnnual General Meeting of the Company

Ref: Regulation 30 and 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

With reference to the above mentioned subject, we enclose the copies of newspaper advertisement published in Financial Express (English) and Business Remedy (Hindi) on 7 September, 2025, regarding e-voting information for 30th Annual General Meeting of the Company to be held on Monday September 29, 2025 at 12:15 P.M (IST).

The above information is also available on the website of the Company at www.srgfin.com.

Kindly take the above information on record and do the needful.

Thanking you,

Yours faithfully,

**For SRG Fingrow Finance Limited
(formerly known as S R G Securities Finance Ltd.)**

**Vinod K. Jain
Managing Director
DIN -00248843**

जीएसटी में बदलाव से सहकारी क्षेत्र और 10 करोड़ डेयरी किसानों को मिलेगा बढ़ावा : सरकार

बिज़नेस रेमेडीज/
नई दिल्ली/आईएनएस

सरकार ने शनिवार को कहा कि ऐतिहासिक बस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधार सहकारी क्षेत्र को मजबूत करेंगे, उनके उत्पादों को प्रतिस्पृष्ठी बनाएंगे, उनके उत्पादों की मांग बढ़ाएंगे और सहकारी समितियों की आय में बढ़ि देंगे।

केंद्र ने प्रमुख क्षेत्रों में जीएसटी में व्यापक कटौती की घोषणा की है जिसका सीधा प्रभाव सहकारी समितियों, किसानों और ग्रामीण उद्यमों पर पड़ा और देश के 10 करोड़ से ज्यादा डेयरी किसानों को लाभ होगा ऐसुधार ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देंगे, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सहकारी समितियों को बढ़ावा देंगे और लाखों विवरों के लिए एक सहकारी बस्तु तक किफायती पहुंच सुनिश्चित करेंगे।

सहकारी तंत्रालय के अनुसार, जीएसटी दरों में कटौती से कृषि और पशुपालन क्षेत्र की सहकारी समितियों को लाभ होगा, इसुधार ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देंगे, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सहकारी समितियों को बढ़ावा देंगे और लाखों विवरों के लिए एक सहकारी बस्तु तक किफायती पहुंच सुनिश्चित करेंगे।